How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2019). Public Expenditure and Fiscal Deficit in Indian Economy
International Journal of Economic Perspectives,*13*(1), 101-106
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय तथा राजकोशीय घाटा

डॉ0 राजेश कुमार श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर – अर्थशास्त्र
जी0डी0 बिनानी पी0जी0 कालेज, मीरजापुर, उत्तर प्रदेश
Email- 1961drs111@gmail.com

सार्वजनिक व्यय बजट का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटे के आकार के निर्धारण तथा सरकार की नीतियों के स्वभाव पर प्रका"ा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक व्यय के आधार पर यह ज्ञात हो पाता है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का कारण राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय है। राजकाषीय घाटे की गंभीरता उस समय अधिक होगी जब कि घाटे की वृद्धि राजस्व घाटे के परिणाम स्वरूप हो। राजको"ाीय घाटे की वृद्धि उस समय आवष्यक रूप से खराब होगी जब कि यह वृद्धि राजस्व घाटे की वृद्धि के कारण हो। और राजस्व व्यय सामाजिक क्षेत्र के उन्नयन या जीवन की गुणवत्ता में सुधार से सम्बन्धित व्ययों जैसे षिक्षा, स्वास्थ्य की तरह नहीं हों। किसी वित्तीय वर्ष में कुल सरकारी आय और कुल सरकारी व्यय का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है, जबकि किसी वित्तीय वर्ष के राजस्व घाटे और सरकार द्वारा लिये गए ऋण पर ब्याज तथा अन्य देयताओं के भुगतान का योग राजकोषीय घाटा कहलाता है। और सरल शब्दों में कहें तो सरकार की कुल आय और व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार को कार्य संचालित करने के लिये कितनी उधारी की ज़रूरत होगी। कुल राजस्व का हिसाब–किताब लगाने में उधारी को शामिल नहीं किया जाता। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है।

उद्देश्य व विधि–

इस लेख के माध्यम से भारत में राजकोषीय घाटे का मूल्यांकन करने के साथ साथ उसके विभिन्न कारणों, प्रभाव तथा सम्भावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत भारत सरकार के वित्त मन्त्रांलय से प्राप्त विभिन्न आंकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, आर्थिक समीक्षा से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात प्रस्तुत लेख में द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है।

© 2019 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. Rajesh Kumar Srivastava**
Submitted: 27 May 2019, Revised: 09 July 2019, Accepted: 18 Sep 2019, Published 30 Dec 2019

How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2019). Public Expenditure and Fiscal Deficit in Indian Economy
International Journal of Economic Perspectives,*13*(1), 101-106
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम ऐक्ट 2003 के लागू होने के बाद केन्द्र तथा राज्यों के राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में गिरावट आयी है। केन्द्र का राजकोषीय घाटा 2002–03 में जो सकल घरेलू उत्पाद का का 5.9 प्रति''ात था 2006–07 में 3.4 प्रति''ात हो गया। **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम** ऐक्ट 2003 ने राजकोषीय घाटे का आने वाले वर्षो अर्थात 2021 तक इसे 3प्रति''ात तक करने का लक्ष्य बनाया।

सारणी – 1, विभिन्न वर्शो में विभिन्न प्रकार के घाटों की स्थिति–

	2013–14	2014–15	2015–16
राजस्व घाटा	–3.1	–2.9	–2.8
राजकोषीय घाटा	–4.4	–4.1	–3.9
प्रभावी राजस्व घाटा	–2.0	–1.0	–2.0
प्राथमिक घाटा	–1.1	–0.8	–0.7

स्रोत आर्थिक समीक्षा– 2015–16

सारणी – 2, केन्द्र सरकार के व्यय

केन्द्र सरकार के व्यय (करोड़ रु0 में)			
मद वार व्यय	2013–14	2014–15	2015–16
(क) गैर योजनागत व्यय	11149021	1213224	1312200
1–व्याज अदायगी	380066	411354	456245
2–रक्षा व्यय	124800	222370	246727
3–सब्सिडीज	245431	266692	243811
4–पें''ान	74076	81705	88521
(ख) योजनागत व्यय	453327	467934	465277
कुल व्यय	1559447	1681158	1777477
राजस्व व्यय	1371772	1488780	1536047
पूॅजी व्यय	187675	192378	241430

स्रोत आर्थिक समीक्षा– 2015–16

© 2019 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. Rajesh Kumar Srivastava**
Submitted: 27 May 2019, Revised: 09 July 2019, Accepted: 18 Sep 2019, Published 30 Dec 2019

How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2019). Public Expenditure and Fiscal Deficit in Indian Economy
International Journal of Economic Perspectives,*13*(1), 101-106
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

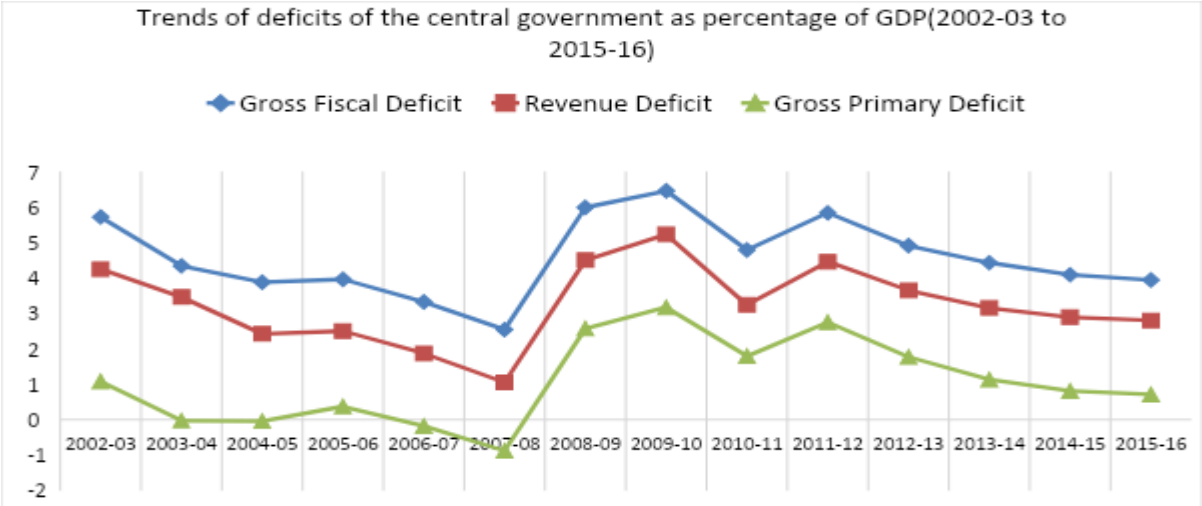

Source: Fiscal Indicators of the Central Government, (As % of GDP), Handbook of Statistics on Indian Economy 2014-15, Reserve Bank of India.

वै”वक स्तर पर भारत के राजकोशीय घाटे की स्थिति–

वै”वक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों और सही मानसून के न होने के कारण भी अर्थव्यवस्था नें 2014–15 में 7.2प्रति”ात और 2015–16 में 7.6 प्रति”ात की मजबूत विकास दर प्राप्त की, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से वि”व में उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गई। क्रय शक्ति समता के अनुसार, वै”वक विकास में भारत का योगदान 2001से 2007 की अवधि में 8.3 प्रति”ात की औसत दर से बढ़कर वर्ष 2014 में 14.4 प्रति”ात हो गया। पिछले साल की तुलना में अप्रैल–फरवरी 2016–17 में राजकोषीय घाटा पूरे साल के घाटे के बजटीय अनुमान का 113.4 प्रतिशत था। अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के बीच केंद्र के कर राजस्व और विनिवेश से मिलने वाले राजस्व में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितना कि कुल व्यय निर्धारित किया गया था। ऐसे में गैर कर राजस्व कम रहने पर वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा पुनरीक्षित लक्ष्य की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक हो सकता है। अप्रैल–फरवरी के दौरान कुल व्यय पुनरीक्षित अनुमान का 90 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 87 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय लक्ष्य का 109 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले साल लक्ष्य का 77 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमान में सरकार ने विनिवेश लक्ष्य बढ़ाकर इसके एक लाख करोड़ रुपए रहने का लक्ष्य रखा है जो बजट अनुमान में 72,500 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष में 11 महीनों के दौरान राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 5.29 लाख करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किये गए। यह 2016–17 के मुकाबल 66,039 करोड़ रुपए अधिक है। इस अवधि में सरकार का कुल व्यय 19.99 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। यह 2017–18 के लिये संशोधित अनुमान का 90.14 प्रतिशत है।

© 2019 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. Rajesh Kumar Srivastava**
Submitted: 27 May 2019, Revised: 09 July 2019, Accepted: 18 Sep 2019, Published 30 Dec 2019

How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2019). Public Expenditure and Fiscal Deficit in Indian Economy
International Journal of Economic Perspectives,*13*(1), 101-106
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

राजकोषीय घाटे मे वृद्धि होने के कारण –

राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है।

- कच्चे तेल का अधिक आयात करने के कारण सरकार के व्यय में वृद्धि होती है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है।
- सोने का अधिक आयात करने से भी राजकोषीय घाटे की मात्रा में वृद्धि होती है।
- सरकारी उधार की अधिक मात्रा होने के कारण अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, जिससे व्यय में वृद्धि होती है।
- सरकार द्वारा खाद्य, उर्वरक, निर्यात मदों आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी के कारण भी सरकार के व्यय में वृद्धि होती है।

राजकोषीय घाटा बढने के प्रभाव

- राजकोषीय घाटा अधिक होने से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा देश की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी जाती है। जिससे निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के बदले में सरकार से अधिक ब्याज की मांग करते है।
- सरकारी प्रतिभूतियों के ना बिक पाने की स्थिति में रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें ख़रीदा जाता है, जिसके लिये रिज़र्व बैंक को और अधिक नोट छापने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।
- रिज़र्व बैंक द्वारा अधिक नोट छापकर राजकोषीय घाटे को कम करने की प्रक्रिया को घाटे का मुद्रीकरण कहते हैं।
- देश की क्रेडिट रेटिंग अच्छी ना होने से आने वाले विदेशी निवेश की मात्रा में भी कमी आती है।
- अधिक राजकोषीय घाटा होने से सरकार ऋण जाल में फंस जाती है, क्योंकि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिये सरकार को ऋण लेना पड़ता है, जिसके ब्याज के भुगतान में अधिक धनराशी खर्च होने से सरकार का राजकोषोय घाटा और भी बढ़ जाता है।
- सरकार द्वारा बैंकों से ऋण लेने के कारण निजी क्षेत्र के लिये ऋण उपलब्ध ना होने से औद्योगिक विकास प्रभावित हो सकता है।
- कुछ लोगों द्वारा राजकोषीय घाटे के यथोचित स्तर को एक सकारात्मक आर्थिक घटना माना जाता है, क्योंकि राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक व्यय कर रही है, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा और मांग में वृद्धि होगी।

© 2019 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. Rajesh Kumar Srivastava**
Submitted: 27 May 2019, Revised: 09 July 2019, Accepted: 18 Sep 2019, Published 30 Dec 2019

How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2019). Public Expenditure and Fiscal Deficit in Indian Economy
International Journal of Economic Perspectives,*13*(1), 101-106
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

- इससे अर्थव्यवस्था का विकास होगा क्योंकि मांग बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, जिससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

राजकोषीय घाटा कम करने के उपाय

राजस्व घाटा कम करने के दो उपाय हैं–

1. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करना।
2. राजस्व व्यय में कमी करना

निश्कर्श–

वर्तमान समय में वि"व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं पर अनिश्चितताओं का आवरण है, भारत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संभावनाओं के साथ उभरा है। लेकिन इन संभावनाओं के साथ एक बड़ी चिंता भी जुडी है। और वह है बढ़ता राजकोषीय घाटा। नि"्चत रूप से भारत में आर्थिक स्तर पर वित्तीय अनुशासन की कमी रही है। अनेक सरकारी विभाग और संगठन वित्तीय अनुशासनहोनता से ग्रस्त रहे हैं, जबकि आर्थिक शक्ति बनने के लिये देश में आर्थिक अनुशासन का वातावरण अनिवार्य रूप से होना चाहिये। बढते हुए वित्तीय अनुशासनहीनता का एक बड़ा दुष्परिणाम है राजकोषीय घाटा। बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे ब्याज दरों के साथ–साथ मुद्रास्फीति दर (महँगाई) भी बढ़ती है। इसीलिये भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्री राजकोषीय घाटे को कम–से–कम रखने पर ज़ोर देते हैं। उनके अनुसार इसके लिये सरकार को अधिक उधार लेने के बजाय सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी कम करने या बेचने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिये तथा देशी–विदेशी निवेशकों को इस ओर आकर्षित करना चाहिये। इनके अलावा सरकार को अपने खर्चों पर अंकुश रखते हुए कर प्रशासन और पूंजी बाज़ार में सुधार करते हुए मुद्रास्फीति और उच्च विकास दर के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अधिक अनुशासित खर्च करने की आदत डालनी चाहिये। राजकोषीय घाटा देश की आर्थिक स्थिति का सूचक होता है। राजकोषीय घाटे का बढ़ता हुआ आकार देश की दयनीय आर्थिक स्थिति की तरफ संकेत करता है। राजकोषीय घाटा यह बताता है कि सरकार की कुल आय एवं कुल व्यय मे कितना अंतर है। प्रत्येक राष्ट्र को राजकोषीय घाटे को समाप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसके लिए सबसे सही उपाय यह है कि सरकार अपने राजस्व घाटे को समाप्त कर दे। राजस्व घाटा समाप्त होने पर राजकोषीय घाटा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

© 2019 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. Rajesh Kumar Srivastava**
Submitted: 27 May 2019, Revised: 09 July 2019, Accepted: 18 Sep 2019, Published 30 Dec 2019

How to Cite:
Dr. Rajesh Kumar Srivastava (Dec 2019). Public Expenditure and Fiscal Deficit in Indian Economy
International Journal of Economic Perspectives,*13*(1), 101-106
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal/article

सन्दर्भ सूची–

- डोर्नबुश आर. और एस. फिशर, 1994 मैक्रोइकोनॉमिक्स, छठा संस्करण, मैक्ग्राहिल।
- मानकिव एन. जी., 2000, मैक्रोइकोनॉमिक्स, चौथा संस्करण, मैकमिलन।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16, 2016–17
- आर0बी0आई0 बुलेटिन, 2015
- De, S. (2012). Fiscal policy in India: Trends and Trajectory. *Ministry of Finance, working paper no. 4751*. Retrieved from http://finmin.nic.in/workingpaper/FPI_trends_Trajectory.pdf
- Karnik, A (2002). Fiscal Policy and Growth. Economic and Political Weekly, 37: 829-31.

© 2019 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Corresponding author: **Dr. Rajesh Kumar Srivastava**

Submitted: 27 May 2019, Revised: 09 July 2019, Accepted: 18 Sep 2019, Published 30 Dec 2019